Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 6, May-2019, ISSN 2230-7540

शहरी व ग्रामीण जनसंख्या में बाल श्रमिकों की रोजगार में सहभागिता का अध्ययन

Dr. Padma Tripathi*

Associate Professor, Economics, K.K.P.G. College, Etawah

सारांश – ***शहरी क्षेत्रों में औसत बाल श्रमिकों की रोजगार सहभागिता से स्पष्ट होता है कि जो व्यवसाय शहर में अधिकतर लोगों द्वारा अपनाये गये हैं जैसे- कृषि, पशुपालन, सिलाई, राजगीरी, रेशम पालन, कुटीर उद्योग, दुकानदारी तथा अन्य में से बाल श्रमिकों की औसत भागीदारी कृषि में 0.20, पशुपालन में 0.20 तथा दुकानदारी में 0.21 है। जबकि राजगीरी (लेबर) 0.13, सिलाई में 0.10, कुटीर उद्योग में 0.06 तथा रेशम पालन में 0.05 है। अन्य व्यवसाय में यह औसत भागादारी 0.10 है।***

अजीतमल शहरी क्षेत्र में कृषि व्यवसाय में 20 परिवारों में से 4 बालक बाबरपुर में 4.2, अटसू में 4.0 तथा अनन्तराम में भी मात्र 4 बालक इस व्यवसाय में अपना हाथ बंटाते हैं। इसी प्रकार पशुपालन में 4 बालक अजीतमल में, बाबरपुर में 4.0 बालक, अटसू में 4.2 बालक तथा अनन्तराम में 4.2 बालक रोजगार में लिप्त रहते हैं।

----------X----------

प्रस्तावना

बहुत से अर्थशास्त्रियों एवं संस्थाओं ने निर्धनता के निर्धारण के लिए अपने-अपने प्रमाप बनाए हैं। इन सभी अध्ययनों का आधार 2250 कैलोरी के बराबर खाद्य का मूल्य है। चूंकि गांवों के लोग स्वयं खाद्यान्नों के उत्पादक हैं, इसलिए शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण लोगों का प्रति व्यक्ति खाद्य-व्यय, रहन-सहन की लागत में अन्तर होने के कारण कम होता है। श्री बी.एस. मिन्हास ही एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1956-57 और 1967-68 के बीच ग्रामों में निर्धनों के प्रतिशत में कमी का संकेत किया है। इसके विरुद्ध पी.डी. ओझा और प्रणव के. बर्धन ने ग्रामीण-निर्धनों के अनुपात में वृद्धि का संकेत किया है। उनके विचार में, परिवर्तन की यह दिशा देश के बढ़ते हुए दरिद्रीकरण की सूचक है। डांडेकर और रथ ने 1960-61 और 1967-68 के दौरान ग्रामीण तथा नगरीय दोनों निर्धन वर्गों में स्थिर अनुपात बताया है। किन्तु इनके अनुमान में ग्रामीण-निर्धनों की संख्या 13.5 करोड़ से बढ़कर 16.6 करोड़ और नगरीय निर्धनों में 4.2 करोड़ से बढ़कर 4.9 करोड़ हो गई।

गरीबी किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के लिए अभिशाप है। इसके निवारण से ही प्रगति का रास्ता खुलेगा। इसीलिये प्रथम पंचवर्षीय योजना से लगातार सरकार इस ओर प्रयासरत है। गरीब अपनी आय का लगभग 80 प्रतिशत भाग भोजन पर खर्च करता है जिसको सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पूरा करने का प्रयास कर रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मध्यम वर्ग उभर कर आया है जो इस बात का द्योतक है कि गरीबी में सुधार हुआ है। यह सुधार सरकार द्वारा प्रायोजित शैक्षिक उपलब्धता, आरक्षण व्यवस्था, महिलाओं व बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने जैसी योजनाओं के कारण सम्भव हुआ है। मार्विन जे. सेट्रोन के कथन के अनुसार 390 मि. भारतीय मध्यम वर्ग में शामिल हैं जो 10 वर्ष पहले गरीबी रेखा से नीचे थे। ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में स्थानान्तरित व्यक्तियों के लिए सरकार शहरी क्षेत्रों में उद्योगों आदि व्यवसायों के माध्यम से रोजगार सृजन कर रही है। जनसंख्या वृद्धि पर कड़ाई से अंकुश लगाना अति आवश्यक है वरना सारे सरकारी प्रयास ऊँट के मुँह में जीरा साबित होंगे। व्यक्तियों में शिक्षा, तकनीकी ज्ञान व वैज्ञानिक सोच का विकास कर लघु व कुटीर उद्योगों को पुनः विकसित किया जाये। कृषि आधारित उद्योगों का विकास कर रोजगार सृजित कर गरीबी उन्मूलन का प्रयास किया जाना चाहिए। जल संरक्षण व सिंचाई के साधनों को विकसित कर मानसून निर्भरता कम करके कृषि उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। उद्योगों का विकेन्द्रीकरण भी रोजगारपरक साबित होगा। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक व आधुनिक शिक्षा प्रणाली

www.ignited.in

विकसित की जाये तो स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यदि स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया जाये तो बेरोजगारी, धार्मिक संकीर्णता, सामाजिक बुराइयों आदि पर विजय पाई जा सकती है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन पूर्ण करने हेतु जनपद की दो तहसीलों को चुना गया जिसमें से प्रत्येक तहसील से एक-एक विकास खण्ड तथा प्रत्येक विकास खण्ड से चार ग्रामीण तथा चार शहरी क्षेत्रों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से बीस-बीस परिवारों को दोनों विकास खण्ड से चयनित किया। सम्पूर्ण अध्ययन प्रक्रिया में चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। कुल मिलाकर 160 ग्रामीण तथा 160 शहरी परिवारों से समंकों को एकत्र कर अध्ययन पूर्ण करने की कोशिश की गई।

नव सृजित जनपद प्राचीन समय से दस्यु प्रभावित रहा है जिसका प्रभाव यहाँ के विकास पर पड़ा है। यहां पर निर्धनता को लेकर अभी तक कोई भी शोध नहीं किया गया है। इस कारण शोध निर्धनता पर किया गया है। यहां का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र अति पिछड़ा है। रोजगार के साधन नगण्य हैं। केवल कुछ प्रतिशत जनसंख्या खेती पर आधारित रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। कृषि में भी पैदावार की स्थिति अधिक ठीक नहीं है। जनपद की मृदा कटाव युक्त, कंकरीली है। नदियों की अधिकता के कारण बीहड़ क्षेत्र अधिक है। जिसके कारण ऊबड़ खाबड़ कटाव, खाइयाँ आदि अधिक हैं। कुछ जगह समतल है वहां पर पैदावार बहुत अच्छी होती है। किसान एक वर्ष में चार-चार फसलें पैदा कर रहे हैं जिसमें नगदी फसलें भी शामिल हैं। सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिसका एक प्रभावित कारण दस्यु प्रभावित क्षेत्र का होना है। अध्ययन के समय समंकों को एकत्र करने में भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने निर्धनता मापने के अनेक आधार माने जिसमें से प्राप्त खाद्य कैलोरी में, प्राप्त सुविधा, परिवार की जनसंख्या, पारिवारिक आय तथा कृषि जोत आदि शामिल हैं।

सूचना के स्रोत तथा समंकों का संग्रहण

प्रस्तुत शोध में 160 ग्रामीण व 160 शहरी परिवार को दैवनिदर्शन विधि से चयनित कर अध्ययन का आधार माना गया। जिसमें दो प्रकार से समंकों को एकत्र किया गया-

(i) प्राथमिक समंकों का संग्रहण-

प्राथमिक समंकों को अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुसूची बनाकर साक्षात्कार द्वारा एकत्र किया गया। जिसमें चयनित परिवार से जानकारी प्राप्त की गयी। जिसमें-मुखिया का नाम, स्त्री, पुरुष तथा बच्चों संख्या, आय-व्यय के साधन, व्यक्तिगत तथा सामूहिक आय, उपभोग स्तर, साक्षरता, ऋण ग्रसतता तथा विभिन्न कुरीतियों के बारे में पूछताछ कर जानकारी ली गयी और तालिकाबद्ध कर शोध में प्रयोग किया गया।

(ii) द्वितीयक समंकों का संग्रहण-

प्रस्तावित शोध से सम्बन्धित प्रकाशित शोध-ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों सरकारी तथा अर्द्धसरकारी कार्यालयों द्वारा प्रकाशित तालिकाओं, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय अखबारों, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित संगोष्ठियों तथा सेमिनार से प्राप्त अध्ययन सामग्री का प्रयोग द्वितीयक समंकों को संग्रहित कर शोध पूर्ण करने में सहायता ली गयी।

साक्षात्कार के समय जो आँकड़े प्रस्तुत हुए उनका लगभग मिलान व स्पष्टीकरण सम्बन्धित सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार करने के पश्चात् ही शोध में प्रस्तुत किया गया।

चयनित क्षेत्र के अध्ययन के लिये चयनित परिवार से प्राप्त जानकारी को तालिकाबद्ध किया गया है। इसी आधार पर कृषि जोत का आकार, परिवार की कुल जनसंख्या तथा उम्र के हिसाब से सदस्यों की जानकारी, रोजगार की स्थिति, शिक्षित रोजगार व अशिक्षित रोजगार की स्थिति, पौष्टिकता स्तर, आय-व्यय का ब्यौरा, ऋण की स्थिति तथा बचत आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

सर्वेक्षण एवं विश्लेषण

शहरी क्षेत्रों में औसत बाल श्रमिकों की रोजगार सहभागिता से स्पष्ट होता है कि जो व्यवसाय शहर में अधिकतर लोगों द्वारा अपनाये गये हैं जैसे- कृषि, पशुपालन, सिलाई, राजगीरी, रेशम पालन, कुटीर उद्योग, दुकानदारी तथा अन्य में से बाल श्रमिकों की औसत भागीदारी कृषि में 0.20, पशुपालन में 0.20 तथा दुकानदारी में 0.21 है। जबकि राजगीरी (लेबर) 0.13, सिलाई में 0.10, कुटीर उद्योग में 0.06 तथा रेशम पालन में 0.05 है। अन्य व्यवसाय में यह औसत भागादारी 0.10 है।

www.ignited.in

अजीतमल शहरी क्षेत्र में कृषि व्यवसाय में 20 परिवारों में से 4 बालक बाबरपुर में 4.2, अटसू में 4.0 तथा अनन्तराम में भी मात्र 4 बालक इस व्यवसाय में अपना हाथ बंटाते हैं। इसी प्रकार पशुपालन में 4 बालक अजीतमल में, बाबरपुर में 4.0 बालक, अटसू में 4.2 बालक तथा अनन्तराम में 4.2 बालक रोजगार में लिप्त रहते हैं।

सिलाई में अजीतमल, बाबरपुर, अनन्तराम में प्रत्येक में 2-2 बालक तथा अटसू में 2.4 बालक कार्य करते हैं। राजगीरी में अजीतमल में 2.4 बालक, बाबरपुर में 2.0 बालक, अटसू तथा अनन्तराम में 3.0-3.0 बालक ही सहभागिता प्रकट करते हैं। रेशम पालन में केवल अजीतमल व बाबरपुर में 2-2 बालक ही औसतन सहभागिता प्रकट करते हैं।

कुटीर उद्योग में अजीतमल में 2 बालक तथा बाबरपुर में 3 बालक श्रमिक कार्य करते हैं। दुकानदारी में 4.2 बालक श्रमिक अजीतमल में, 4.2 श्रमिक, बाबरपुर में, 4.4 श्रमिक अटसू में तथा 4.4 श्रमिक अनन्तराम में कार्य कर रहे हैं। अन्य व्यवसाय जैसे सब्जी बेचना, फल बेचना आदि में अजीतमल, बाबरपुर तथा अनन्तराम में 2.0 बाल श्रमिक तथा अटसू में 2.4 बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

अजीतमल में सर्वाधिक बाल श्रमिकों की भागीदारी दुकानदारी में 4.2 कृषि तथा पशुपालन में 4-4 है। कुल अपनाये गये व्यवसायों में बीस परिवारों की कुल 92 जनसंख्या में से मात्र 3 प्रतिशत बाल श्रमिक इस शहर में हैं।

बाबरपुर में सर्वाधिक बाल श्रमिक 4.2 कृषि में, 4.0 पशुपालन में व्यस्त हैं। दुकानदारी में भी इनकी भागीदारी लगभग कृषि के बराबर 4.2 है। कुल बाबरपुर में 20 परिवारों की जनसंख्या 100 में से 3 प्रतिशत बाल श्रमिक ही औसतन कार्यरत हैं।

अटसू में बाल श्रमिकों की स्थिति इस प्रकार है- कृषि में 4.0, पशुपालन में 4.2, सिलाई में 2.4, राजगीरी में 3.0, दुकानदारी में 4.4 तथा अन्य में 2.4; कुल 102 औसत 20 परिवारों की जनसंख्या में से 2.5 प्रतिशत बाल श्रमिक ही व्यस्त हैं।

अनन्तराम शहरी क्षेत्रों में 4.0 बाल श्रमिक कृषि में, 4.2 पशुपालन में, 2.0 सिलाई में, 3.0 राजगीरी में, 4.4 दुकानदारी में तथा 2.0 अन्य में व्यस्त हैं। कुल 109 औसत 20 परिवारों की संख्या में से बाल श्रमिक की भागीदारी 2.2 प्रतिशत है।

अ (1) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औसत बाल श्रमिकों की रोजगार में सहभागिता

तालिका नं.- अ- (i) शहरी क्षेत्रों में औसत बाल श्रमिकों की रोजगार सहभागिता

शहर का नाम / व्यवसाय		अजीतमल	बाबरपुर	अटसू	अनन्तराम	औसत सहभागिता
कृषि	औसत	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20
	कुल	4.00	4.20	4.00	4.00	4.00
पशुपालन	औसत	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20
	कुल	4.00	4.00	4.20	4.20	4.00
सिलाई	औसत	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10
	कुल	2.00	2.00	2.40	2.00	2.00
राजगीरी	औसत	0.12	0.10	0.15	0.15	0.13
	कुल	2.40	2.00	3.00	3.00	2.60
रेशम पालन	औसत	0.10	0.10	-	-	0.05
	कुल	2.00	2.00	-	-	1.00
कुटीर उद्योग	औसत	0.10	0.15	-	-	0.06
	कुल	2.00	3.00	-	-	1.20
दुकानदारी	औसत	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21
	कुल	4.20	4.20	4.40	4.40	4.20
अन्य	औसत	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10
	कुल	2.00	2.00	2.40	2.00	2.10
औसत	औसत	0.14	0.15	0.13	0.12	0.13
	कुल	2.80	3.00	2.60	2.40	2.60

सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि कृषि, पशुपालन तथा दुकानदारी में बाल श्रमिक का काफी जुड़ाव है। पिछड़े होने के कारण लोग बालकों को इन कार्यों में व्यस्त कर लेते हैं जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी प्रकार कर सकें।

तालिका नम्बर-अ-(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की रोजगार सहभागिता में अजीतमल विकास खण्ड में सांफर, जगन्नाथपुर, फूलपुर तथा मोहारी की स्थिति शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में औसत 0.33, पशुपालन में 0.28, सिलाई में 0.10, राजगीरी में 0.18, कुटीर उद्योग में 0.05, दुकानदारी में 0.18 तथा अन्य व्यवसाय में 0.17 औसत सहभागिता है। सांफर गांव में सर्वाधिक सहभागिता औसत 0.32 कृषि से है, पशुपालन से 0.28, राजगीरी, दुकानदारी, अन्य से औसत 0.18, 0.18 है। सिलाई से 0.10 औसत है। कुल मिलाकर 103 सदस्यों में से 3.8 सदस्य बाल श्रमिक रोजगारी में अपनी भागीदारी रखते हैं जो कुल का 3.68 प्रतिशत है।

फूलपुर में बाल श्रमिकों की सर्वाधिक भागीदारी कृषि में 0.34 है। कुल 20 परिवारों की औसत जनसंख्या 100 में से 3.6 बालक श्रमिक रूप में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हैं। कृषि में औसतन 0.34, पशुपालन में औसत 0.29, राजगीरी तथा दुकानदारी में औसत 0.18 प्रत्येक में, अन्य में 0.16, सिलाई में 0.10 औसत बाल श्रमिक कार्यरत हैं।

www.ignited.in

मोहारी ग्राम में 20 परिवारों की औसत 102 जनसंख्या में से औसतन 3.6 बालक विभिन्न व्यवसायों में लिप्त हैं। कृषि में औसतन 0.33 तथा पशुपालन 0.28, 0.20 राजगीरी से, 0.18 दुकानदारी से, 0.16 अन्य व्यवसाय से तथा 0.10 सिलाई से बाल श्रमिक जुड़ कर परिवार की आय का साधन बन रहे हैं। कुल जनसंख्या में बाल श्रमिकों का योगदान 3.53 प्रतिशत है।

जगन्नाथपुर में 20 परिवारों की कुल जनसंख्या 98 में से बाल श्रमिकों का रोजगार से जुड़ाव 3.9 प्रतिशत का है जिसमें कृषि में 6.4, पशुपालन में 5.6, सिलाई में 2.0, राजगीरी में 3.6, कुटीर उद्योग में 2.0, दुकानदारी में 3.6 तथा अन्य में 3.8 बाल श्रमिक जुड़े हुए हैं। सर्वाधिक औसत 0.32 कृषि से तथा 0.28 पशुपालन से है।

तालिका नं.- अ- (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में औसत बाल श्रमिकों की रोजगार सहभागिता

गाँव का नाम / व्यवसाय		सौंफर	फूलपुर	मौहारी	जगन्नाथपुर	औसत सहभागिता
कृषि	औसत	0.32	0.34	0.33	0.32	0.33
	कुल	6.40	6.80	6.60	6.40	6.60
पशुपालन	औसत	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28
	कुल	5.60	5.80	5.60	5.60	5.60
सिलाई	औसत	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	कुल	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
राजगीरी	औसत	0.18	0.18	0.20	0.18	0.18
	कुल	3.60	3.60	4.00	3.60	3.60
रेशम पालन		-	-	-	-	-
कुटीर उद्योग	औसत	0.10	-	-	0.10	0.05
	कुल	2.00	-	-	2.00	1.00
दुकानदारी	औसत	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
	कुल	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
अन्य	औसत	0.18	0.16	0.16	0.19	0.17
	कुल	3.60	3.20	3.20	3.80	3.40
औसत	औसत	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18
	कुल	3.80	3.60	3.60	3.80	3.60

सभी ग्रामों में सभी व्यवसाय का कुल औसत देखने से स्पष्ट होता है कि कृषि में 0.33 सर्वाधिक जुड़ाव बाल श्रमिकों का है। इसके बाद पशुपालन से 0.28, राजगीरी से 0.18, दुकानदारी से 0.18, अन्य से 0.17, सिलाई से 0.10 तथा कुटीर उद्योग से 0.05 औसतन जुड़ाव बाल श्रमिकों का क्रमशः है।

चूंकि गांवों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन ही है इसलिए इन व्यवसाय में अधिकतर बाल श्रमिक हैं जो परिवार के साथ जीविका कमाने में सहयोग करते हैं।

महिला पुरुष रोजगार भागीदारी के सम्बन्ध में दोनों विकास खण्डों में आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि प्रत्येक आयु वर्ग में औसतन शहरों तथा गांवों में पुरुषों की रोजगार भागीदारी महिलाओं से अधिक है, विशेषकर 18-50 आयु वर्ग में। शायद इस आयु वर्ग में लोग कार्य योग्य हैं व अपनी जिम्मेदारी परिवार के प्रति समझते हैं। इसलिए महिला तथा पुरुष की रोजगार भागीदारी लगभग बराबर की है। अजीतमल विकास खण्ड में 0-10 आयु वर्ग में गांव तथा शहर दोनों में भागीदारी बराबर की है। इसका कारण है कि अजीतमल शहर भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए शायद बच्चे कृषि, पशुपालन तथा दुकानदारी में अपनी छोटी सी भूमिका प्रस्तुत करते हैं, ऐसा गरीबी के कारण हो सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. वर्किंग ग्रुप मिनिस्टरी ऑफ एग्रीकल्चर (1994): "एवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टॉक फार कन्जमसन"
2. अभिताभ तिवारी (1996-97): "भारत में शिक्षा, विशेष रूप में महिलाओं के सम्बन्ध में", "वार्ता" (XVII) अप्रैल-अक्टूबर, पृ.सं. 115-123.
3. रंजन राय (2000): "पॉवर्टी हाउसहोल्ड, साइज एण्ड चाइल्ड वैलफेयर इन इण्डिया", इकोनोमिक एण्ड पोलीटिकल वीकली, सितम्बर 23, पृ.सं. 3511
4. जी.सी. त्रिपाठी एवं राकेश कुमार पाण्डेय (2001): "इम्पैक्ट ऑफ डवलपमेन्ट ऑन वेजेस एण्ड इम्पलाइमेन्ट ऑफ रूरल लेवर इन इण्डिया", वार्ता (XXI) अप्रैल से अक्टूबर, पृ.सं. 13-25.
5. गवर्नमेन्ट ऑफ उ.प्र. (2002): "दसवीं पंचवर्षीय योजना", वॉल्यूम I तथा II
6. वर्ड बैंक (2002): "इण्डिया-पॉवर्टी इन इण्डिया" दि चेलेंज ऑफ उ.प्र.
7. सुभ्राभ्रता भट्टाचार्या (2003): "रूरल मार्केटिंग-दि हाल एक्सपीरियेन्स", हिन्दू सर्वे ऑफ इण्डियन, इन्डस्ट्री
8. एस.पी. तिवारी (2005): "एलीवेशन ऑफ पॉवर्टी इन उ.प्र. एनुअल कॉन्फ्रेन्स", यू.पी. इको. एसो., 18-19 दिसम्बर
9. हिमांशू शेखर सिंह एवं पंचाली सिंह (2005): "रूरल इण्डिया अपॉरच्युनिटी एण्ड चैलेन्ज" एनुअल कॉन्फ्रेन्स, यू.पी. इकोनॉमिक एसोसियेशन, 18-19 दिसम्बर, पृ.सं. 28-37

www.ignited.in

10. अशोक कुमार (2006): "ग्रामीण भारत में लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति", कुरुक्षेत्र, नवम्बर, पृ.सं. 5.

11. उमेश चन्द्र अग्रवाल (2006): "बाल श्रमिक की विभीषिका", कुरुक्षेत्र, नवम्बर, पृ.सं. 32.

12. नरैनी सिंह जोशी (2006): "ग्रामीण बाजार", योजना, अप्रैल, पृ.सं. 25-29

13. ब्रजेश कुमार तिवारी (2006): "बाल श्रमिक अस्तित्व की खोज में", कुरुक्षेत्र, नवम्बर, पृ.सं. 40.

14. योगेन्द्र के. अलख (2006): "भारतीय कृषि समस्यायें और सम्भावनायें", योजना, अगस्त, पृ.सं. 17-24.

15. राकेश शर्मा (2006): "बाल श्रम उन्मूलन के लिये आवश्यकता है- वैकल्पिक रोजगारी की", कुरुक्षेत्र, नवम्बर, पृ.सं. 42

15. वाई.एस.पी. थोराट (2006): "सहकारी ऋण संस्थाओं का पुनर्जीवन", योजना, अगस्त, पृ.सं. 43-46

17. सुभाष सेतिया (2006): "रोजगार के क्षेत्र में महिलायें", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 43.

18. शान्ता सिन्हा (2006): "गरीबों के लिये शिक्षा का हक", योजना, नवम्बर, पृ.सं. 15-19

19. देवी सेट्ठी (2006): "सहकारी कृषक स्वास्थ्य कार्यक्रम यशस्विनी", योजना, अप्रैल पृ.सं. 38

20. शंकर दयाल शर्मा (2007): "बीस सूत्रीय कार्यक्रम और ग्रामीण विकास", योजना, जनवरी, पृ.सं. 42

21. इन्दिरा राजारमण (2007): "ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिलायें", योजना, मई, पृ.सं. 28.

22. एस नारायण (2007): "रोजगार सम्भावना पर एक नजर", योजना, अप्रैल, पृ.सं. 25.

23. मथुरा स्वामी (2007): "खाद्य एवं पोषण असुरक्षा को कम महत्व", योजना, मई, पृ.सं. 13.

24. उमेश चन्द्र अग्रवाल (2008): "कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 35.

25. अपराजिता पाण्डया (2008): "जड़ी बूटी का रास्ता"

26. अखिल कुमार मिश्र (2008): "कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनायें", कुरुक्षेत्र, फरवरी, पृ.सं. 24-28.

27. किरन बेदी (2008): "महिला सशक्तिकरण-कुछ विचार", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 15.

28. कुमारी रूपम (2008): "बाल विकास एवं पोषण", योजना, नवम्बर, पृ.सं. 23.

29. जवाहर लाल गुप्ता (2008): "ग्रामीण गरीबी एवं रोजगार के बदलते स्वरूप", कुरुक्षेत्र, फरवरी, पृ.सं. 8.

30. निर्मल कुमार आनन्द (2008): "कुपोषण निवारण का सहकारी प्रयास", कुरुक्षेत्र, अक्टूबर, पृ.सं. 45.

31. मंजुला गर्ग एवं पुनीत कुमार (2008): "महिला अस्मिता की चुनौती", योजना, मार्च, पृ.सं. 65.

32. रत्ना कपूर (2008): "वैश्यावृत्ति की रोकथाम और महिला मानवाधिकार", योजना, फरवरी, पृ.सं. 13-14.

33. रत्ना श्रीवास्तव (2008): "बालिका शिक्षा की स्थिति", योजना, सितम्बर, पृ.सं. 31.

34. रहीस सिंह (2008): "गरीबी निर्धारण का अर्थशास्त्र", योजना, नवम्बर, पृ.सं. 47.

35. कुमारी रूपम (2008): "बाल विकास एवं पोषण" योजना, नवम्बर, पृ.सं. 23-24

36. सोना दीक्षित व अरुण कुमार दीक्षित (2008): "हिंसक होता बचपन", योजना, नवम्बर, पृ.सं. 25-26

37. सुधीश कुमार पटेल (2008): "कृषि में रोजगार के बढ़ते अवसर", कुरुक्षेत्र, फरवरी, पृ.सं. 4-6

38. संगीता कुमार (2008): "अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 19

39. रोहनी वी.एस. तथा जयराम भट्ट (2009):"रूरल डवलपमेन्ट एफर्ट इन इण्डिया", इकोनोमिक एफेयर वाल्यूम 45, 4 दिसम्बर, पृ.सं. 199-202

40. अंगद सिंह (2010): "गरीबी निवारण-समस्या और समाधान के रास्ते" नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट

www.ignited.in

पावर्टी डिबेट, भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, नवम्बर, पृ.सं. 12-13.

41. डा. डी. देवनाथन (2010): "पॉवर्टी एलीवेशन प्रोग्राम एण्ड दलित इम्पावरमेन्ट इन तमिलनाडु", नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट पॉवर्टी डिबेट इन इण्डिया, भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, इलाहाबाद, नवम्बर पृ.सं. 16-17.

42. डा. विनीता सिंह (2010): "प्रोब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन ग्लोबलाइजेशन्ड विलेज", नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट पॉवर्टी डिबेट इन इण्डिया, भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, इलाहाबाद, नवम्बर, पृ.सं. 40-41.

43. डा. सलायमा जोव एण्ड टोमी वर्गीज (2010): "रोल ऑफ वूमेन इम्पावरमेन्ट इन पॉवर्टी एरेडीकेशन एण्ड सोशियो इकोनोमिक चेन्ज इन केरल", नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट पॉवर्टी डिबेट, भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, इलाहाबाद, नवम्बर, पृ.सं. 15-16

44. पद्मा त्रिपाठी (2010): "भारत में निर्धनता की स्थिति का आकलन", नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट पॉवर्टी डिबेट", भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, इलाहाबाद, नवम्बर, 20, 21, पृ.सं. 8-9.

45. पहलाद कुमार (2010): "भारत में गरीबी उन्मूलन में मनरेगा की प्रासंगिकता", नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन रिसेन्ट पॉवर्टी डिबेट इन इण्डिया, भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, इलाहाबाद, नवम्बर, पृ.सं. 36-37.

46. नवीन पंथ (2010): "गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा", योजना, पृ.सं. 15.

47. अमर उजाला (2011): "भारत में गरीबी" दिनांक 09.07.2011

48. अरविन्द केजरीवाल (2011): "भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था का अधिकार", योजना, अप्रैल, पृ.सं. 13.

49. अजीत कुमार सिंह (2011): "उ.प्र. के ग्रामीण निर्धन में भूमि वितरण का प्रभाव", योजना, नवम्बर, पृ.सं. 28-30.

50. अरुण कुमार वर्मा (2011): "मीडिया एवं सामाजिक परिवर्तन", योजना, अगस्त, पृ.सं. 34.

51. आनन्द कुमार खरे (2011): "बाल श्रम की समस्या एवं निवारण", नेशनल सेमीनार, 29-30 जनवरी, तिलक महाविद्यालय, औरैया

52. एन.सी. सक्सेना (2011): "कृषि भूमि में महिलाओं का उत्तराधिकारी हक", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 11.

53. गौरव कुमार (2011): "बढ़ती आबादी के लिये खाद्यान्न उपलब्धता", योजना, जुलाई

54. जयराम रमेश (2011): "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नसंस्थापन विधेयक", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 7.

55. दिव्या पाण्डेय (2011): "मानवाधिकार एवं कन्या भ्रूण हत्या", योजना, अप्रैल, पृ.सं. 43

56. पद्मा त्रिपाठी (2011): "महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता", नेशनल सेमीनार, तिलक महाविद्यालय, औरैया

57. पद्मा त्रिपाठी (2011): "भारत में निर्धनता की वास्तविकता एवं निवारण", अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी, 4, 5, 6 मार्च, वार्ष्णेय कालेज, अलीगढ़, पृ.सं. 9-10.

58. मुकेश शर्मा एवं सुषमा अग्रवाल (2011): "निर्धनता उन्मूलन में रोजगारपरक शिक्षा का महत्व", अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी, 4, 5, 6 मार्च, वार्ष्णेय कालेज, अलीगढ़, पृ.सं. 8-9.

59. टाइम्स ऑफ इण्डिया रिपोर्ट (2011): "पॉवर्टी सिचुयेशन इन इण्डिया", 1 अप्रैल 2011

60. डी.पी. सिंह (2011): "माइग्रेशन पॉवर्टी एण्ड डवलपमेन्ट इन उ.प्र."

61. रेनू गुप्ता (2011): "नई सदी में भारत-बाल श्रम एक चुनौती", नेशनल सेमीनार, 29-30 जनवरी, तिलक महाविद्यालय, औरैया, पृ.सं. 11-12

62. लीला विसारिया (2011): "भारत की 15वीं जनगणना", योजना, जुलाई, पृ.सं. 6-9

63. वेद प्रकाश अरोरा (2011): "जनगणना का दशकीय सफर", योजना, जुलाई

www.ignited.in

64. सरस्वती राजू (2011): "बाल लिंग अनुपात-उभरते प्रतिमान", योजना, जुलाई, पृ.सं. 13-19

65. सुभाष शर्मा (2011): "सेवा क्षेत्र में बाल मजदूरी", योजना, सितम्बर, पृ.सं. 17

66. साहब सिंह (2011): "भारत में गरीबी निवारण और आर्थिक विकास – चुनौतियां एवं समस्या समाधान", अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी, 4, 5, 6 मार्च, वार्ष्णेय कालेज, अलीगढ़, पृ.सं. 7

67. शभ्य आलम एवं निर्भय सिंह (2011): "बाल श्रम एक अनसुलझी समस्या", नेशनल सेमीनार, 29-30 जनवरी, तिलक महाविद्यालय, औरैया, पृ.सं. 108-109

68. अजय कुमार सिंह (2012): "ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण", योजना, अक्टूबर, पृ.सं. 23.

69. अशिमा गोयल (2012): "पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन और भविष्य", योजना, जनवरी, पृ.सं. 45.

70. ममता मोहन (2012): "सशक्तिकरण-एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण", योजना, जून, पृ.सं. 43.

71. बजट (2011-12): भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

72. टी.आर. जैन, मुकेश त्रिहान तथा राजू त्रिहान (2012): "भारतीय आर्थिक समस्यायें", पृ.सं. 89-99

73. एफ.ए.ओ. कारपोरेट डाक्यूमेन्ट (रीजनल आफिस फॉर एशिया एण्ड पेसीफिक) "इण्डियन एक्पीरियेंस आन हाउसहोल्ड फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी"

Corresponding Author

Dr. Padma Tripathi*

Associate Professor, Economics, K.K.P.G. College, Etawah